

निग/२९५९/II/15

1

न्यायालय-श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)



Rs. 20/-

343  
10.8.15

विनोद कुमार पिता शिवप्रसाद मिश्रा (ब्राम्हण) निवासी ग्राम सहुआर  
तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र० .....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

- 1-संजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
- 2-संतोष कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
- 3-बृजेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सभी निवासी ग्राम सहुआर  
तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०
- 4-म०प्र० शासन .....अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

श्री. राजेश मिश्रा  
जन्म नाम दिनांक 20.8.15  
प्रमाण किया गया।

सिद्धि  
सिद्धि कोर्ट रीमा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर  
सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० के राजस्व  
प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2013-14 मे  
पारित आदेश पत्रिका (आईर शीट)  
दिनांक-17.07.2015

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत किया जा रहा है:-

- 1-यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रिका (आईर शीट)  
दिनांक-17.07.2015 विधि प्रक्रिया के विपरीत व प्राकृतिक न्याय  
सिद्धांतो के खिलाफ होने से निरस्तगी योग्य है।

M

B

Q


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0-2959/दो/15

जिला-सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश विनोद कुमार/संजय कुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-12-2015	<p>1- प्रकरण में आवेदक अभि० श्री राकेश मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया ।</p> <p>2- यह निगरानी प्रकरण अपर कलेक्टर सिंगरोली के प्र०क्रमांक-02/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक-17.7.15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>3- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया ।</p> <p>निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से मात्र यह आदेश दिया गया है कि उत्तरवादी तलब हों, एवं मूल प्रकरण आहूत हो । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की वर्तमान में कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है ।</p> <p>अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दारि. हो ।</p>	1

  
सदस्य 12-15